शहरः दावणगेरे

राज्यः कर्नाटक

श्रेणीः व्यापार और औद्योगिक केंद्र, टायर 3 तथा इससे नीचे

दावणगेरे, मध्य कर्नाटक का एक शहर है, जिसे हाल ही में जनवरी 2007 में शहरी नगर निगम का दर्जा दिया गया था। दावणगेरे वर्तमान में अपने जिले (जिसे दावणगेरे भी कहा जाता है) का अकेला नगर निगम है, जिसे वर्ष 2006 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारत के 250 सबसे अधिक पिछड़े जिलों में से एक के रूप में चिन्हित किया था। दावणगेरे (गरीबी के संदर्भ में) कर्नाटक के उन पांच जिलों में से एक है जिन्हें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम (बीआरजीएफ) से निधियां प्राप्त होती हैं। शहर के सबसे प्रसिद्ध उद्योगों में कपड़ा और कृषि प्रसंस्करण शामिल हैं। हाल ही में, दावणगेरे उच्च शिक्षा के एक केन्द्र के रूप में उभर रहा है और इस एजेंडे के एक हिस्से के रूप में, इस क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की एक शाखा स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं।

1. जनसांख्यिकी प्रोफाइल (रूपरेखा)

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
कुल जनसंख्या	434971	23625962	377,106,125
यूए की कुल जनसंख्या (यदि)			
जिला शहरी आबादी में यूएलबी आबादी की हिस्सेदारी (%)	69.15		
जनसंख्या वृद्धि दर (एईजीआर) 2001-11	1.77	2.74	2.76
क्षेत्र (वर्ग मीटर)*	77.12		
जिले में यूएलबी क्षेत्र का हिस्सा (%)*#	1.30		
जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति वर्ग प्रति किमी)*	5640		
साक्षरता दर (%)	84.90	85.78	84.11
अनुसूचित जाति (%)	12.44	12.61	12.60
अनुसूचित जनजाति (%)	6.17	3.47	2.77

युवा, 15-24 वर्ष (%)	20.61	19.78	19.68
स्लम जनसंख्या (%)	13.79	1.60	17.36
कार्य आयु समूह, 15-59 वर्ष (%)	66.68	67.04	65.27

स्रोतः भारत की जनगणना, 2011

*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

#एक से अधिक जिले में फैले हुए शहरी स्थानीय निकाय

2. आर्थिक प्रोफाइल

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
2004-05 के स्थायी कीमत पर प्रति व्यक्ति आय (रु.)*	30219	43266	रु. 35,947[a]
शहरी गरीबी का अनुपात (शहरी आबादी का %)**	23.76	15.3	13.7
बेरोजगारी दर, 2011-12***	3.64	2.9	3.4
कार्य करने वालों की दर, 2011-12***	31.68	37.6	35.5
कार्य की स्थिति, 2011-12 (प्रतिशत)*** स्व नियोजितः नियमित/मजदूरी वेतनभोगी कर्मचारीः अनौपचारिक श्रम।	 47.49 40.26 12.25	 39.2 44.9 15.9	 42.0 43.4 14.6
मजदूरों का क्षेत्रवार वितरण, 2011-12 (प्रतिशत)*** प्राथमिक द्वितीय तृतीयक	 15.38 21.68 62.94	 8.1 28.9 63.0	 7.5 34.2 58.3
प्रमुख व्यवसायों द्वारा मजदूरों का वर्गीकरण, 2011-12 (प्रतिशत)*** व्यवस्थापक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक व्यवसाय	 28.38 7.86 2.51	 28.5 12.1 6.5	 15.8 8.8 6.7

तकनीशियनों और एसोसिएट पेशेवर क्लर्क सेवा श्रमिक और दुकान एवं मार्केट सेल्स श्रमिक कुशल कृषि एवं मत्स्य श्रमिक शिल्प और संबंधित ट्रेडों के श्रमिक प्लांट और मशीन ऑपरेटरों और संयोजनकर्ता (अस्सेम्ब्लेर्स) एलिमेंटरी व्यवसाय श्रमिक कब्जे से वर्गीकृत नहीं	4.40 15.09 13.77 12.80 4.03 11.14 0	5.6 8.0 5.1 16.0 6.6 11.7 0	5.0 14.7 4.6 19.2 9.2 16.1 0.1
प्राथमिक वस्तु निर्माता#	कपड़े		
प्रमुख उद्योग##	स्टील के तार, सुगर, कपास याम		
अनुमोदित एसईजेड की संख्या	0	60	413

नोटः 2009-10, 2010-11, 2011-12 का 3 वर्ष औसत

स्रोतः *सभी भारत- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय

**राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की यूनिट लेबल डाटा, भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय, 68वां राउंड, 2011-12

***राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की इकाई स्तर डेटा, भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति, 68वां राउंड, 2011-12

#जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

##जिला औद्योगिक प्रोफाइल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारत सरकार

∞ वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

3. अवसंरचना स्थिति

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
घर के अंदर नल के पानी का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत (बनाये गए स्रोतों से)	82.45	68.39	84.14
बिजली के उपयोग के साथ घरों का %	97.10	96.42	92.68

घर के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों का %	82.34	71.57	72.57
गंदे पानी के माध्यमों का ड्रेनेज से जुड़े परिवारों का प्रतिशत	94.85	87.60	81.77
सीवरेज प्रणाली का प्रकार*	भूमिगत सीवरेज प्रणाली		
ठोस अपशिष्ट प्रणाली का प्रकार*	द्वार से द्वार		
कम्प्यूटर/लैपटॉप का इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत कम्प्यूटर/लैपटॉप का बिना इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत	5.10 12.96	10.96 12.63	8.27 10.40
मोबाइल फोन के उपयोग के साथ घरों का %	65.01	64.79	64.33
आवास का स्वामित्व पैटर्न (%) स्वामित्व किराए पर	 51.87 44.92	 51.05 46.05	 69.16 27.55
भीड़भाड़ वाले घरों में रहने वाले परिवारों का %	33.54	35.10	32.94
संकेतक	**शहर (नगर निगम)**		
प्रति 1,00,000 लोगों पर अस्पतालों की संख्या*	.23		
प्रति 1,00,000 लोगों पर स्कूलों की संख्या*			
प्राथमिक	51		
माध्यमिक	45		
द्वितीयक	37		
महाविद्यालय	16		

स्रोतः मकान, घरेलू सुविधाओं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

4. राजनीतिक प्रोफाइलः नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचा

शासन की वास्तुकला *चुने गए एवं कार्यकारी निकायों की संरचना। पदानुक्रम के संकेत दें।*	दावणगेरे नगर निगम (डीसीसी) हुबली और धारवाड़ दोनों जुड़वां शहरों के नागरिक बुनियादी ढांचे और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। दावणगेरे नगर निगम (डीसीसी) के दो स्कंध हैं अर्थात विचार-विमर्श स्कंध और कार्यकारी स्कंध। कार्यकारी स्कंध की एक निर्वाचित परिषद होती है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित एक महापौर और वार्ड पार्षद शामिल होते हैं। इसमें 41 वार्ड हैं और एक निर्वाचित प्रतिनिधि प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है। आयुक्त, जो निगम का कार्यकारी प्रमुख भी होता है, प्रशासनिक स्कंध का प्रधान होता है। उसको राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। नगर निगम नागरिकों के लिए सेवाओं और मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है, जिसमें शामिल हैं: सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था; साफ-सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता; सार्वजनिक पार्क और उद्यानों का रखरखाव; व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना; भवन निर्माण के विनियमन; और वाणिज्यिक गतिविधियों के लाइसेंस आदि शामिल हैं। जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था संबंधी कार्य कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड (केयूडब्ल्यूएसडीबी), द्वारा किया जा रहा है, जो जल आपूर्ति से संबंधित मुख्य परियोजनाओं की देखरेख करता है। गंदी बस्तियों को हटाने और सुधार की जिम्मेदारी कर्नाटक स्लम क्लीयरेंस बोर्ड (केएससीबी) की है। कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड सस्ती लागत पर कर्नाटक के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। शहरी कार्य योजनाओं का निष्पादन कर्नाटक राज्य नगर नियोजन बोर्ड और नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाता है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के रखरखाव और सरकारी इमारतों के निर्माण और रखरखाव सहित सड़क निर्माण कार्यों के लिए जिम्मेदार है। नगर प्रशासन निदेशालय (डीएमए) शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। यह नगर पालिकाओं

	के कामकाज की निगरानी, उपयुक्त मानव संसाधन विकास नीति निर्माण, नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के ऊपर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखने, शहरी स्थानीय निकायों की कर वसूली की निगरानी, व्यय में पारदर्शिता के लिए नीतियां निर्धारित करने, नगर पालिकाओं के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने, शहरी स्थानीय निकायों को सरकार से मिली राशि हस्तांतरित करने के साथ-साथ एसजेएसआरवाई (शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए), आईडीएसएमटी, और निर्मल नगर परियोजना जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) एक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने वाली एजेंसी है, जो उद्योगों के व्यवस्थित विकास के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। समाज कल्याण निदेशालय (डीएसडब्ल्यू) राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
<u>निर्वाचित प्रतिनिधियों की सं.</u>	41
<u>निर्वाचन विवरण*</u> *चुनाव चक्र, पिछला चुनाव, नाम, जहां प्रासंगिक हो पार्टी की संबद्धता, मुख्यमंत्री, आयुक्त एवं महापौर के लिए कार्यालय ग्रहण करने की तारीख।*	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। उन्हें 13 मई 2013 को निर्वाचित किया गया था। श्री बी.एच. नारायणप्पा आयुक्त हैं। परिषद का नेतृत्व आईएनसी की महापौर श्री एच बी गोनेप्पा द्वारा किया जाता है।

स्रोतः *संबंधित यूएलबी वेबसाइट और मीडिया सर्च

<u>5. शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) का कार्यनिष्पादन</u>

क्रेडिट और कर

शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग (नवम्बर 2012 तक)*	

संपत्ति कर#	कवरेज (%): संग्रह क्षमता (%): राशि (रु.):

स्रोतः *www.jnnurm.nic.in

#रिफॉर्म मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

शहरी स्थानीय निकायों में ई-शासन एवं कम्प्यूटरीकरण

सुधार	**स्थिति (कार्यान्वित, प्रगति में और किसी भी टिप्पणी में)**
संपत्ति कर*	प्रगति में
लेखांकन*	कार्यान्वित
जल आपूर्ति और अन्य सुविधाएं*	कार्यान्वित
जन्म और मृत्यु पंजीकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रम*	कार्यान्वित
नागरिक शिकायत निगरानी*	कार्यान्वित
कार्मिक प्रबंधन प्रणाली*	कार्यान्वित
निर्माण योजना अनुमोदन*	प्रगति में
ई-प्रापण	कार्यान्वित
क्या नागरिक अपने बिल एवं करों का भुगतान सिटिजन फैसिलिटी सेन्टर (सीएफसी) पर कर सकते हैं?#	हाँ
क्या शहरी स्थानीय निकायों पर भुगतान करने की ऑनलाइन सुविधा है#	नहीं
शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग किया जाने वाला ई-मेल सॉफ्टवेयर क्या है#	एनआईसी
क्या शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय लोकल एरिया नेटवर्क	हाँ

(एलएएन)/वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं#	
क्या आप स्टेट डाटा सेन्टर (एसडीसी) का उपयोग करते है?#	नहीं
क्या शहरी स्थानीय निकाय की स्वयं की वेबसाइट है#	हाँ
74वैं सीएए का कार्यान्वयन#	1 कार्यों को अभी भी हस्तांतरित किया जाना शेष है अर्थात् अग्नि सेवाएं

नोटः *शहरी स्थानीय निकाय में ई-गवर्नेंस के मॉड्यूल कार्यान्वित

स्रोतः *सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइट #शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

मान्यता

राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सम्मानों, पुरस्कारों, पायलटों, क्षैतिज नेटवर्कों की सूची।	

6. वित्तीय एवं स्वास्थ्य

वित्तीय

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग के साथ घरों का %*	53.28	64.35	67.77

वित्तीय स्थिति#		
नगर निगम के आय और व्यय का विवरण (लाख रु. में)	आय	व्यय

2009-10	44082.59	47633.47
2010-11	35087.27	36307.97
2011-12	33119.82	33841.44
नगरीय गरीबों के लिए आरक्षित बजट का प्रतिशत@	33% गरीबों के लिए आवंटित किया गया है, जिसे आगे अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबन्धित शहरी गरीबों के लिए 22.75% और अन्य शहरी गरीबों के लिए 7.25% और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 3% के रूप में बांटा गया है।	

स्रोतः *मकान, घरेलू सुविधाएं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

#शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

@जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट

पर्यावरण

स्वच्छ भारत रैंकिंग*	लागू नहीं
उपलब्ध शहरों के लिए व्यापक पर्यावरण आकलन#	लागू नहीं

स्रोतः *प्रेस सूचना ब्यूरो, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2015

#केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, 2009

7. क्षमताः ट्रैक रिकार्ड और पहल

जेएनएनयूआरएम परियोजनाएं	स्थिति या टिप्पणी
बीएसयूपी/आईएचएसडीपी	
यूआईजी/यूआईडीएसएसएमटी	यूआईडीएसएसएमटीः कुल 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी तथा दोनो प्रगति पर है।
परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	3464

परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	कुल लागत (लाख रु. में)	कुल स्वीकृत परियोजनाओं में क्षेत्र की हिस्सेदारी
	सीवरेज	1	336	9.7
	परिवहन	1	3128.4	90.3
केन्द्र द्वारा जारी सहायता का हिस्सा (प्रतिशत)	97.55			
पूरा किए हुए कार्य का प्रतिशत (वास्तविक प्रगति)	81			
उपयोग किया गया वित्त (प्रतिशत)	104.09			

स्रोतः www.jnnurm.nic.in (नवम्बर, 2015 तक पहुंच)

शहरी विकास मंत्रालय की योजनाओं के साथ एकत्रीकरण	स्थिति, टिप्पणी
विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय)	
अमृत	कवर है
जेएनएनयूआरएम	कवर था
एनयूआईएस	कवर है
पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)	

स्रोतः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार